

कानपुर में बनेगा देश का पहला मेगा लेदर पार्क

451 करोड़ आएगी लागत

सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की हरी झंडी

अमर उजाला व्यूरो

लखनऊ। कानपुर में मेगा लेदर पार्क की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। कानपुर के रमईपुर गांव में 235 एकड़ में बनने वाले इस लेदर पार्क पर 451 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस मेगा लेदर पार्क में 5850 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लगभग दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जल्द ही इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह देश का पहला लेदर पार्क होगा।

कानपुर के रमईपुर में प्रस्तावित मेगा लेदर पार्क को पिछले दिनों खाजिवा मंत्रालय की सहमति मिल गई है। अब सीएम के हाथों इस परियोजना के शिलान्यास की तैयारी है। शिलान्यास के बाद मेगा लेदर क्लस्टर



235

एकड़ भूमि
रमईपुर गांव में
अधिग्रहीत की गई

पार्क की स्थापना से कानपुर देश के दस बड़े लेदर मैनुफैक्चरिंग राज्यों में अपना स्थान और बेहतरी करने में सफल होगा। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले लेदर पार्क में 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

दो लाख को
मिलेगा रोजगार

जर्बिक डेड लाइव लोग परोक्ष रूप से रोजगार पाएंगे। इस पार्क में डेड सै से अर्धक टेनरी इकाइयों काया करेगी। चमड़े से बने जूते, पर्स, बैकेट से लेकर अन्य विविधस्तरीय उत्पाद तैयार करके उनका निर्यात किया जा सकेगा। लेदर पार्क सभी तरह की सुविधाओं से लैस होगा। इसमें लेदर प्रोडक्ट के उत्पादों के प्रदर्शन की व्यवस्था भी होगी। यहाँ नहीं लेदर पार्क में उत्पादों को खरीदने के लिए आने वाले दुनिया भर के निवेशकों के रुकने और खाने-पीने की व्यवस्था भी होगी। पार्क में कैटेन से लेकर रेंटहाउस तक बनेंगे। गंगा नदी में प्रदूषण न हो, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। पार्क में कारोबार करने वालों को 1000 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट मिल सकेंगे।

डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड कंपनी यहाँ विकास कार्य शुरू करेगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से यहाँ विकास के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चमड़े संबंधी सारी इकाइयों के एक जगह होने से गंगा में होने वाला प्रदूषण बड़ा मुद्दा भी नहीं रहेगा।

काभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर फिर विश्व के मानचित्र पर औद्योगिक शहर के रूप में मान्यता उपरिपति दर्ज कराएगा। सरकार कानपुर की औद्योगिक शहर के रूप में खोई पहचान को लौटाने की कजबद में जुटी है। सीएम के दिशा-निर्देशन में मेगा लेदर

क्लस्टर प्रोजेक्ट तैयार हुआ। इसके लिए कानपुर के रमईपुर गांव में 235 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई। फिर एमएसएमई विभाग के जरिये केंद्र सरकार के खाजिवा मंत्रालय को मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मंजुरी के लिए भेज गया, जिसे हरी झंडी मिल गई है।